



स्टार्टअप की संवृद्धि: भारत के विकास को बढ़ावा

यह एडिटरियल 12/09/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "[Making India a start-up nation](#)" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारितंत्र की चर्चा की गई है और घातीय वृद्धि एवं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के वज़िन की प्राप्ति के लिये शिक्षा, उद्यमिता एवं रोज़गार के तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रलिस के लिये:

[भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम](#), [उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग](#), [डिजिटल इंडिया](#), [एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस](#), [स्टार्टअप इंडिया](#), [स्टैंड अप इंडिया](#), [वैकल्पिक निवेश कोष](#), [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#), [विक्रम-S](#), [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2024](#)।

मेन्स के लिये:

भारत के स्टार्टअप क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, भारतीय स्टार्टअप के विकास से संबंधित चुनौतियाँ।

भारत के पास अब विश्व का [तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र](#) है, जिसमें **140,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप शामिल हैं और प्रत्येक 20 दिनों पर एक यूनिकॉर्न का उभार** हो रहा है। यह वृद्धि शीर्ष-स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी पूंजीगत व्यय और व्यापक इंटरनेट पैठ द्वारा समर्थित है। हालाँकि, इस गति को बनाए रखने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के वज़िन को प्राप्त करने के लिये [शिक्षा](#), [उद्यमिता](#) एवं [रोज़गार](#) को और अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

विकास की व्यापक संभावना मौजूद है, विशेष रूप से यदि भारत के स्टार्टअप पारितंत्र की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से की जाए। यदि **5% भारतीय सनातक भी वैश्विक रुझानों के अनुरूप उद्यमिता का विकल्प चुनते हैं तो इससे सालाना 50,000 नए स्टार्टअप उभर** सकते हैं, जिससे संभावित रूप से लाखों रोज़गार अवसर सृजित हो सकते हैं। इसे साकार करने के लिये भारत को अपने उच्च शिक्षा मेट्रिक्स पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जहाँ पारंपरिक नियोजन (प्लेसमेंट) दरों के साथ-साथ उद्यमिता पर भी बल दिया जाना चाहिये। [एकरेखीय दृष्टिकोण से शिक्षा](#), [उद्यमिता](#) एवं [रोज़गार](#) को एकीकृत करने वाले एक सहकरियात्मक प्रतमान की ओर संक्रमण के माध्यम से भारत अपने 'अमृत काल' के दौरान घातीय आर्थिक विकास पर लक्ष्यित हो सकता है।

भारत के स्टार्टअप क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- पारस्थितिकी तंत्र का आकार और विकास:** भारत एक मज़बूत स्टार्टअप पारस्थितिकी तंत्र रखता है, जो [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग \(DPIIT\)](#) के तहत **1.4 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप** के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
 - इस गतिशील पारस्थितिकी तंत्र की विशेषता इसकी तीव्र वृद्धि है, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रतिदिन अधिक स्टार्टअप का योग कर रही है।
 - इसके अलावा, **पछिले सात-आठ वर्षों में प्रत्येक 20 दिनों में एक यूनिकॉर्न (unicorn) का उभार** भारतीय स्टार्टअप परदृश्य में अपार संभावनाओं और उद्यमशीलता की भावना को उजागर करता है।
- रोज़गार सृजन:** भारतीय स्टार्टअप पारस्थितिकी तंत्र रोज़गार सृजन का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है, जहाँ **DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 15.5 लाख** से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार अवसर पैदा कर रहे हैं।
 - अकेले **2023 में ही इन स्टार्टअप ने 3.9 लाख नौकरियों** का सृजन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.6% की उल्लेखनीय वृद्धि और पिछले **पाँच वर्षों की तुलना में 217.3% की व्यापक वृद्धि** को दर्शाता है।
 - यह **प्रवृत्ति रोज़गार के अवसर प्रदान करने** और देश के आर्थिक विकास में योगदान करने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- आर्थिक योगदान:** स्टार्टअप का प्रभाव रोज़गार सृजन से कहीं आगे तक वसित है, जहाँ उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
 - वर्तित वर्ष 2023 में स्टार्टअप और उनके कॉर्पोरेट समकक्षों ने 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण निवेश** किया, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। यह पर्याप्त योगदान आर्थिक विकास और नवाचार के प्रमुख चालकों के रूप में स्टार्टअप की भूमिका को उजागर करता है।

भारत का स्टार्ट-अप क्षेत्र कनि कारणों से वृद्धि कर रहा है?

- **डिजिटल अवसरचना क्रांति:** **'डिजिटल इंडिया'** जैसी पहलों के नेतृत्व में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के व्यापक अंगीकरण से स्टार्ट-अप के लिये अनुकूल माहौल का निर्माण हुआ है।
 - **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** एक 'गेम-चेंजर' सिद्ध हुआ है, जिसके तहत अगस्त 2024 तक लेनदेन मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
 - इस डिजिटल ढाँचे के साथ-साथ विश्व में नमिनतम डेटा लागत (वर्ष 2023 में औसतन 6.7 रुपए प्रति GB) ने स्टार्ट-अप को कुशलतापूर्वक विशाल ग्राहक आधार तक पहुँचने में सक्षम बनाया है।
- **सहायक सरकारी नीतियाँ:** **'स्टार्ट-अप इंडिया'** और **'स्टैंड अप इंडिया'** जैसी पहलों के माध्यम से भारत सरकार का सक्रिय रुख महत्त्वपूर्ण रहा है।
 - 30 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार, DPIIT ने 1,40,803 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिससे उन्हें कर लाभ और सरल अनुपालन मानदंड जैसी सुविधा प्राप्त होती है।
 - 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार, स्टार्ट-अप के लिये फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) के तहत 99 वैकल्पिक निवेश फंड्स (Alternative Investment Funds- AIFs) को 7,980 करोड़ रुपए प्रदान किये गए।
- **बढ़ता प्रतिभा पूल:** भारत का जनसांख्यिकी लाभांश, जहाँ 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, स्टार्ट-अप के लिये एक विशाल प्रतिभा पूल प्रदान करता है।
 - उभरती प्रौद्योगिकियों पर अधिकाधिक ध्यान देने के साथ भारत प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक तैयार कर रहा है।
 - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता पर बल दिया गया है, जो इस 'टैलेंट पाइपलाइन' को और संवृद्ध कर रहा है।
- **परिष्कृत होता वित्तपोषण पारितंत्र:** वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के स्टार्ट-अप वित्तपोषण पारितंत्र ने प्रत्यास्थता का प्रदर्शन किया है।
 - जबकि वर्ष 2023 में वित्तपोषण में गरिवट ('funding winter') देखी गई, वर्ष 2024 में इसमें पुनः उछाल आया। भारतीय टेक स्टार्ट-अप ने वर्ष 2024 की पहली छमाही (H1) में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो वर्ष 2023 की दूसरी छमाही (H2) से 4% अधिक है। इस प्रकार भारत स्टार्ट-अप क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक वित्तपोषण देश बना हुआ है।
 - घरेलू उद्यम पूंजी फर्मों के उदय और वैश्विक निवेशकों के प्रवेश से वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता आई है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट अवसर:** 'क्लीनटेक', 'स्पेसटेक' और 'डीपटेक' जैसे उभरते क्षेत्र नवाचार की अगली लहर को आगे बढ़ा रहे हैं।
 - अंतरिक्ष क्षेत्र को नज्दी हतिधारकों के लिये खोलने के सरकार के निर्णय से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र म्येचर 2023 में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिये 124.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ।
 - नवंबर 2022 में स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) द्वारा भारत के पहले नज्दी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S के सफल परिक्षण ने इस क्षेत्र में एक मील के पत्थर को चहिनति किया।
- **बढ़ता घरेलू बाज़ार:** विश्व आर्थिक मंच (IMF) के अनुसार स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत में वर्ष 2030 तक 140 मिलियन मध्यमवर्गीय परिवार होंगे, जो स्टार्ट-अप के लिये एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करेगा।
 - बढ़ती प्रयोज्य आय और बदलते उपभोक्ता व्यवहार सभी क्षेत्रों में मांग को बढ़ा रहे हैं।
 - ग्रांट थॉरन्टन (Grant Thornton) के अनुसार, भारत में ई-कॉमर्स का मूल्य वर्ष 2025 तक 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **कॉरपोरेट और स्टार्ट-अप का तालमेल:** स्थापित कॉरपोरेट्स और स्टार्ट-अप के बीच बढ़ते सहयोग से दोनों पक्षों के लिये लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं।
 - कई बड़े भारतीय समूहों ने 'स्टार्ट-अप एक्सेलरेटर' या 'वेंचर फंड' स्थापित किये हैं।
 - उदाहरण के लिये, रलियांस इंडस्ट्रीज की जियोजेननेक्सट (JioGenNext) ने 170 से अधिक स्टार्ट-अप को समर्थन दिया है।
 - वर्ष 2021 में टाटा डिजिटल द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी '1mg' का अधिग्रहण इस तरह के सहयोग की क्षमता को परिलक्षित करता है।

स्टार्ट-अप के विकास की राह की प्रमुख बाधाएँ

- **नियामक बाधाएँ:** जटिल और कभी-कभी अस्पष्ट नियामक वातावरण स्टार्ट-अप के लिये गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
 - उदाहरण के लिये, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं के वर्गीकरण पर हाल की बहस ने परिचालन संबंधी अनिश्चितताएँ उत्पन्न की हैं।
 - हाल ही में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2024 यद्यपि आवश्यक है, लेकिन इससे स्टार्ट-अप पर अनुपालन का बोझ बढ़ गया है।
- **प्रतिभा प्रतिधारण की बाधा:** यद्यपि भारत बड़ी संख्या में स्नातक तैयार करता है, लेकिन शीर्ष प्रतिभा का प्रतिधारण (Talent Retention) एक चुनौती बनी हुई है।
 - प्रतिभाओं को बनाए रखने में स्टार्ट-अप क्षेत्र को स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा और विदेशी अवसरों के प्रलोभन का सामना करना पड़ रहा है।
 - रैंडस्टैड (Randstad) द्वारा वर्ष 2023 में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि 60% भारतीय तकनीकी पेशेवर बेहतर करियर की संभावनाओं के लिये विदेश जाने को तैयार हैं।
 - वर्ष 2021 में अमति नैयर द्वारा पेटीएम (Paytm) छोड़ने जैसे हाई-प्रोफाइल मामले प्रतिभा प्रतिधारण के मुद्दे को उजागर करते हैं।
- **बाज़ार संतृप्ति और अति-प्रतिस्पर्द्धा:** भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे तीव्र

प्रतस्पर्द्धा और कम लाभ मार्जनि की स्थिति बिन रही है।

- 'एडटेक' कषेत्र को महामारी के बाद मंदी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण BYJU's और Unacademy जैसी कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी।

• यह अत-प्रतस्पर्द्धा प्रायः असंवहनीय नकदी हानि और बाज़ार समेकन की ओर ले जाती है।

- अवसंरचना में अंतराल और असमान वित्तपोषण: यद्यपि भारत ने डिजिटल अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी पर्याप्त अंतराल बना हुआ है।
 - यहाँ तक कि शहरी कषेत्रों में भी इंटरनेट की पहुँच 71% ही है; इस प्रकार, आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे वंचित है।
 - शहरी-ग्रामीण डिजिटल वभाजन बहुत अधिक है, जहाँ ग्रामीण कषेत्रों में इंटरनेट घनत्व शहरी कषेत्रों के 69% की तुलना में महज 37% है।
 - यह असमानता कई डिजिटल स्टार्ट-अप के लिये उपलब्ध बाज़ार को सीमति करती है। उदाहरण के लिये, एग्रीटेक स्टार्ट-अप देहात (DeHaat) अपनी सफलता के बावजूद ग्रामीण किसानों के बीच सीमति इंटरनेट पहुँच के कारण वसितार में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
 - इसके अलावा, वित्तपोषण में वृद्धि के बावजूद यह व्यापक रूप से असमान बना हुआ है। उदाहरण के लिये, भारत में महिलाओं द्वारा संचालित 6000 से अधिक स्टार्ट-अप वित्तपोषित नहीं हैं।
- 'स्केलिंग' की चुनौतियाँ: कई भारतीय स्टार्ट-अप अपनी शुरुआती सफलता से आगे बढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं। परचालन अक्षमताओं से लेकर नए बाज़ारों में वसितार करने में कठिनाइयाँ तक कई समस्याएँ मौजूद हैं।
 - आँकड़े दिखाते हैं कि स्टार्ट-अप कषेत्र की प्रबल वृद्धि के बावजूद लगभग 90% भारतीय स्टार्ट-अप पहले पाँच वर्षों के भीतर वफिल हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से 'स्केलिंग' या परचालन पैमाने को बढ़ाने से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है।
- डीप टेक नवाचार का अभाव: यद्यपि भारत नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल के सृजन में उत्कृष्ट क्षमता रखता है, डीप टेक नवाचारों में वह पीछे है।
 - भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% था, जबकि अमेरिका में यह 3.5% था।
 - यह अंतराल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन जैसे कषेत्रों में स्पष्ट है, जहाँ वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना की घोषणा के बावजूद इस कषेत्र में कुछ ही स्टार्ट-अप सक्रिय हैं।
 - उद्योग-अकादमिक सहयोग की कमी इस मुद्दे को और भी गंभीर बना देती है। भारत में लगभग 40,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में से 1% से भी कम उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं।
- निकास संबंधी चुनौतियाँ: भारतीय स्टार्ट-अप पारस्थितिकी तंत्र अभी भी नविशकों के लिये व्यवहार्य निकास विकल्प प्रदान करने में संघर्ष कर रहा है।
 - वर्ष 2023 में 46 IPOs की पेशकश की गई, जिनसे कुल 41095.36 करोड़ रुपए जुटाए गए। यह वर्ष 2022 में 40 IPOs के माध्यम से जुटाए गए 59301.7 करोड़ रुपए से 30% कम है।
 - कुछ सूचीबद्ध स्टार्ट-अप के फीके प्रदर्शन ने नविशकों और संस्थापकों दोनों को सतर्क कर दिया है।

भारत में स्टार्ट-अप कषेत्र को संवृद्ध करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' को सुव्यवस्थिति करना: RBI के फनितेक सैंडबॉक्स की सफलता से प्रेरणा लेते हुए सभी कषेत्रों में एक व्यापक वनियामक सैंडबॉक्स लागू किया जाए।
 - इससे स्टार्ट-अप को पूर्ण वनियामक बोझ के बनिा नयितरति वातावरण में नवोन्मेषी उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति मिलेगी।
 - इस मॉडल को हेल्थटेक, एडटेक और क्लीनटेक जैसे कषेत्रों तक वसितारित किया जाए।
- लक्षति कौशल विकास कार्यक्रम: उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षावर्तियों के सहयोग से कषेत्र-वशिष्ट कौशल विकास पहल शुरू की जाए।
 - AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार के 'स्कलि इंडिया' कार्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है और उसका वसितार किया जा सकता है।
- वकिंद्रीकृत स्टार्ट-अप हब: लक्षति अवसंरचना और प्रोत्साहनों के माध्यम से टयिर-2 एवं टयिर-3 शहरों को स्टार्ट-अप हब के रूप में वकिसति किया जाए।
 - इसे मोहाली के सफल स्टार्ट-अप पारतंत्र पर मॉडल किया जा सकता है, जसिमें 2021 और 2023 के बीच स्टार्ट-अप पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
 - एक 'हब-एंड-स्पोक मॉडल' (hub-and-spoke model) क्रयान्वति किया जाए, जहाँ प्रत्येक प्रमुख शहर (हब) आसपास के छोटे शहरों (स्पोक) को सहयोग प्रदान करें।
- उन्नत कर प्रोत्साहन: सभी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिये कर लाभ को वर्तमान तीन वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाकर पाँच वर्ष किया जाए।
 - डीप टेक स्टार्ट-अप और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधति करने वाले स्टार्ट-अप के लिये अतिरिक्त कर छूट लागू की जाए।
 - उदाहरण के लिये, इज़राइल द्वारा प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रदत्त कर लाभों (जिनमें 12% की नमिन कॉर्पोरेट कर दर भी शामिल है) ने उनके स्टार्ट-अप पारस्थितिकी तंत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है।
 - भारत में भी इसी प्रकार का मॉडल लागू करने की आवश्यकता है।
- सुदृढ़ IP संरक्षण ढाँचा: पेटेंट फाइलिंग एवं अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थिति किया जाए, जहाँ नयोजति औसत समय को कम किया जाए।
 - महत्त्वपूर्ण कषेत्रों में स्टार्ट-अप के लिये फास्ट-ट्रैक परीक्षण शुरू किया जाए। प्रत्येक वर्ष स्टार्ट-अप की बड़ी संख्या को लक्षति करते हुए IP जागरूकता कार्यक्रम लागू किया जाए।
 - जापान की त्वरति परीक्षण प्रणाली, जसिमें पेटेंट परीक्षण के समय को औसतन 14 माह तक कम कर दिया है, एक आदर्श के रूप में कार्य कर सकती है।
- सरकारी खरीद को बढ़ावा: MSMEs से मौजूदा 25% सरकारी खरीद की आवश्यकता के समान स्टार्ट-अप से भी सरकारी खरीद का एक

नश्चिति प्रतशित अनविर्य कथि जल ।

- अडेरकल की संघीय सरकर दवलरल 23% प्रडुख सरकरल अनुडंध छुटे वुववसलरुं कु प्रदलन करने कल लकुषुड डरलत के लथि डी एक डेंचडरकु हु सुकतल है ।
- इससे डरलतुड सुटरुट-अडुस के लथि संडरवलतल रूड से अरडुं डुल्लर कल डरलर खुल सुकतल है ।
- कुषुतुर-वशिशुट इनकुडुडेशन कुंदर: उदुडुडुग जगत के अगुरणी लुगुं के सहडुडुग से कुषुतुर-वशिशुट इनकुडुडेशन कुंदर सुथरडतल कथि जलरुं ।
- सुडुसुटेक, डरडुुडेक अरु कलुनडेक जैसे कुषुतुरुं पर धुडरन कुंदरतल कथि जल । उदरहरण के लथि, हुंदररडरड डें 'टी-हुड' (T-Hub) की सुडलतल कल कुषुतुर-वशिशुट डुकुस के सुथ अनुसरण कथि जल सुकतल है ।
- सुटरुटअड-अकलदडकल सहडुडुग डुंड: सुटरुट-अड अरु अकलदडकल/शुकुषणकल संसुथरनुं के डीच सहडुडुग कु सुवधलजनुक डनरने के लथि एक ररषुटुरीय डुंड कल नररडरण कथि जल ।
- इसे डुरतलन के 'जुडरन हुसुतुरररण डरगीदररी' (Knowledge Transfer Partnerships) जैसे सुडल कररुडुडुडुं के अरुधर पर तैडर कथि जल सुकतल है ।
- वरुष 2025 तक प्रतविरुष 1,000 ऐसे सहडुडुग कु सुगड डनरने कल लकुषुड नररुधररतल कथि जल ।
- उनुनत वतलतडुडुषण डहुंडुडु: सुटरुट-अडुस के लथि डुंड अडुडु डुंडस (FFS) कल वसुतलर कथि जल अरु कुषुतुर-वशिशुट डुंड कल सुजन कथि जल ।
- डुकु के 'अंटरडुररइजु डरइनुस गररुटी' के सुडरन डरलत डें डी सुटरुट-अड ःरुणुं के लथि कुरेडुटे गररुटी डुडनुनल शुरु की जल ।
- वरुष 2025 तक सडुी गरुं वुं डें हुई-सुडुीड इंटरनेट कनेकुटवलतल सुनशुचलतल करने के लथि डरलतनेट (BharatNet) जैसे डललुं के कररुडरनुवडन डें गतल लरई जल । अडुरडुकुत डरलररुं तक सुटरुट-अडुस की डहुंडुडु के लथि डल अतुडुंत डलहतुतुवडुडुण है ।
- डुजलतल कलरुडररुी डरहुलु कु डदरवल देने डें असुटुनथल के 'ई-रेजीडेंसी कलरुडुडुडु' की सुडलतल डरलत के लथि डी एक डुंडल के रूड डें कलरुड कर सुकतल है ।

नशुकरुष

डरलत के सुटरुट-अड डररसुथतलकल तंतुर ने अडर संडरवनुअरुं दखलरई है अरु अररुथकल वकलस अवं रुरुजगरर सुजन डें डलहतुतुवडुडुण डुगदलन कर रल है । हुलरुं कल, इस गतलकु डनरल अखने अरु इसे तेज करने के लथि वनलथलडक डरधररुं कु दूर करनुनल, शकुषल अवं उदुडुग के डीच गहन सहडुडुग कु डदरवल देनुनल अरु वतलतडुडुषण अवं अवसंरकनुनल तक सुडरन डहुंडुडु सुनशुचलतल करनुनल अरुवशुडुडु है । डरलत शकुषल, उदुडुडुडु अवं रुरुजगरर कु अकीकुत कर अडुनी उदुडुडुडुलतल कुषडतल कु सुकरर कर सुकतल है अरु वरुष 2047 तक एक वकलसतल ररषुटुर डनरने की अरु अरुग डद सुकतल है ।

अडुडुडुडु डुरशुन: डरलत डें तेजुी से डदते सुटरुट-अड डररसुथतलकल तंतुर के डरडुरेकुषुड डें डतलइडे डल डरलतुड अरुथवुडुवसुथर के लथि कुनुन-सुी डुरडुख कुनुनुतलथल अरु अवसर डुरसुतुत करतल है? सरकरर अरु नलत नरररडुडुडु इस डररसुथतलकल तंतुर कल लरड कसल डुरकरर उठल सुकते है तलकलसततु अवं सुडरवेशी वकलस सुनशुचलतल कथल जल सुके?

UPSC सवलल सेवल डुरीकुषल, वगत वरुष के डुरशुन (PYQs)

डुरशुन. वेंकुर कुडुडुडु से तलतुडुरडु है: (2014)

- (A) उदुडुगुं कु डुरदलन की जलने वलली एक अलुडकललकल डुंडुी
- (B) नअ उदुडुडुडुडु कु डुरदलन की गई दलरुघकललकल सुटरुटअड डुंडुी
- (C) नुकसलन के सुडुडु उदुडुगुं कु डुरदलन की गई धनररशु
- (D) उदुडुगुं के डुरतसुथरडन अरु नवुीनीकरण के लथल डुरदलन की गई धनररशु

उतुतर: (B)